SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I request the Labour Minister and the Chief Commissioner. Yesterday there was teargas against the sweepers. May I request you to kindly convey our feelings to the hon. Minister of Home Affairs to intervene in the matter and find out a settlement.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत सिंचाई और बिजली मन्त्री का ध्यान नार्थ एवेन्यु के फ्लैट नं० 93 से लेकर 216 मे कल रात 9 बजे से अभी पार्लमेंट में आने तक बिजली की रोशनी गुल है रात भर अंधेरे मे रहना पड़ा, उसकी ओर दिलाना चाहता हू। हमने बार बार शिकायत की नार्थ एवेन्यु एन्क्वायरी आफिस को, उन्होंने आगे बात की लेकिन कोई असर नही पडा? अभी तक हम अंधेरे मे है। इसके बारे मे जल्दी कार्यवाही करे ताकि अंधेरा खत्म हो और बिजली सभी जगह आ जाये।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Though the sweeper population is not directly involved in the process of production, if the city does not remain clean and healthy, it is likely that the health of the rest of the population such as industrial workers will be affected and to that extent our production equipment would be adversely affected. I suggest that the Government should take note of this. I do not want to make any political capital out of this because the Jan Sangh is associated with this or that. Without bringing politics into picture, I would urge that the Government should act promptly and see that justice is done.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): This is a matter which concerns the health and sanitation of the entire city, capital. We do not want to make any political capital out of it; we shall certain communicate to the Ministers concerned the feelings of the House expressed by many Members.

12.24 hrs

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1972-73—contd.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान इस समय भयकर अकाल के दौर से गुजर रहा है। 26 जिलो मे से 23 जिलो से भयकर अकाल की स्थिति है और राजस्थान के करीब करीब 25 हजार गाव इससे प्रभावित है। राजस्थान सरकार की दुर्भाग्य से जो आर्थिक स्थिति बन गई है उसकी ओर मैं वित्त मत्री महोदय का खास तौर से ध्यान दिलाना चाहूगा। राजस्थान पर करीब सात सौ करोड का कर्जा है जिस पर अकेले ब्याज का भुगतान करीब-करीब 45 करोड का होता है। इस का परिणाम यह हो रहा है कि राजस्थान मे विकास का काम बिल्कुल बन्द हो गया है। वहा अकाल के कार्यों पर भी इस का कुप्रभाव पड रहा है। स्थिति यह है कि जो राजस्थान का पुराना फेमीन कोड है, जो आज से पचास साल पहले बना था और जिस मे दुर्भाग्य से आप ने परिवर्तन करने की बात सोची नहीं, उस के मुताबिक मजदूरों के लिये मजदूरी का जो प्रावधान है वह एक रुपया, सवा रुपया और डेढ रुपया है। आप जानते हैं कि आज एक, सवा या डेढ रुपये में किसी

[श्री नवल किशोर शर्मा]

का पेट नहीं भर सकता । गल्लो की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, खास तौर से बाजरा, ज्वार आदि जो मोटे अनाज कहलाते है उन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। वे पिछले दिनो में 100 रुपये क्विटल तक पहुच गई । दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति भी इतनी खराब है कि वह अपनी तरफ से कुछ कर नही सकती। जब महाराष्ट्र मे अकाल पीडितो के लिए 3 रुपया मजदूरी मिलती है, मध्य प्रदेश मे 2 रुपये मिलती है, लेकिन राजस्थान मे वही एक, सवा या डेढ रुपया मिलता है। इस का परिणाम यह है कि जो गरीब तबका है, उस की हालत बहुत खराब है। मुझे आशंका है कि अकाल के दिनो मे राजस्थान मे शायद कुछ लोग भूख से भी मरने लग जायं। इस लिये मै वित्त मत्री से कहना चाहता हू और आप के माध्यम से प्रधान मत्री से भी निवेदन करना चाहता हू कि राजस्थान को स्पेशल असिस्टेंट की जरूरत है। आज जरूरत इस लिये नही है कि राजस्थान के लोगो ने या सरकार ने रिलीफ एफर्टस नही किये है, बल्कि राजस्थान की आज हालत यह है कि पहले बहुत सालों से अकाल की परिस्थितियां रही है और उसके कारण वहा की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन हो गई है तथा इस बारे मे सोचने की बडी जरूरत है।

इस के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर रिलीफ मेजर्स बिल्कुल बंद हो गये हैं क्योंकि मैटिरियल कम्पोनेंट्स के लिये राजस्थान सरकार के पास एक दम पैसा नहीं है और आप की सरकार मैटिरियल कम्पोनेन्ट्स के लिये कुछ पैसा नही देती। इस का परिणाम यह है कि जितने भी छोटे काम हैं, जिन को लेने की योजना बनाई जा सकती है, वह काम था तो पिछले दिनो मे पूरे हो चुके है या मैटीरियल कम्पोनेन्ट्स वाले काम है। इस का परिणाम यह हो रहा है कि बावजूद इसके कि राजस्थान में भयकर अकाल की स्थीति है इस तरह के जो रिलीफ वर्क्स है वह वहा पर बिलकुल बद होरहे है। इस बारे मे भी विचार करने की आवश्यकता है कि आज केन्द्रीय सरकार अकाल पर करोडो रुपये खर्च करती है लेकिन मैटीरियल कम्पोनेन्ट्स के नाम पर कुछ नही देती है। इस का परिणाम यह हुआ है कि परमानेंट नेचर के काम जो हो सकते थे वह नहीं हो सकते। मेरा समझ में नही आता कि आखिर सरकार के सोचने का क्या तरीका है। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगर मैटीरियल कम्पोनेन्ट्स नही दिये जाते है तो वहा परमानेंट नेचर के काम नही हो सकते। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हू कि इस बारे मे गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

जहा तक फाडर का सवाल है उसकी हालत भी खराब है। मवेशियो के लिये चारा नही है। अंग्रेजो के जमाने में जब राजस्थान मे अकाल पड़ते थे तब हमेशा पशु सिंध आदि प्रातो मे निकल जाया करते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उस का सहारा भी बद हो गया। जब राजस्थान मे फैमिन है तब गुजरात से भी फैमिन है, महाराष्ट्र मे और मध्य प्रदेश के बहुत से हिस्सों में भी फैमिन है। इस लिये मवेशियों के चरने के लिये कहीं पर जगह नहीं

है । जो राजस्थान का वेस्टर्न इलाका है उस की सारी एकानमी ही मवेशियो पर आधारित है । वह एनिमल हस्बैन्ड्री की एकानिमी है । इस लिये राजस्थान मे फाडर के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, वर्ना सारे इलाके में जो भी बढ़िया क़िस्म का पशुधन है वह समाप्त हो जायेगा ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूगा कि यह सही है कि राजस्थान की राज्य सरकार के पास या केन्द्रीय सरकार के पास मोटे गल्ले का स्टाक नही है। बाजरा और ज्वार का भी शायद उनके पास अधिक स्टाक नही है। यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हू कि चूकि हमारे इलाके वैस्टर्न राजस्थान मे मोटे गल्ले का खाना अधिक चलता है इस लिये अगर कही और से इस तरह का गल्ला ले कर वहा पर भेजने की व्यवस्था की जा सकती हो तो वह की जानी चाहिये ।

राजस्थान से राजस्थान नहर के साथ-साथ पशुपालन के बारे मे जब तक आप एक्सटैन्सिव तोर पर काम शुरू नही करेंगे, और केन्द्रीय सरकार इस बारे मे ध्यान नही देगी अथवा ट्यूबैल के रिग्ज आदि के लिये विशेष रूप मे व्यवस्था नही करेगी तब तक राजस्थान के अकाल का मुकाबला करना मुझ काफी कठिन दिखाई देता हे । अभी तो शुरूआत हुई है । आगे आने वाले समय म काफी कठिन महीने आने वाले है इस लिये इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूगा । दुर्भाग्य से यहा राजस्थान मे भीषण अकाल रहा है, वहीं भरतपुर और सवाईमाधोपुर का क्षेत्र ऐसा रहा है यहा इस साल फ्लड्स से बहुत बडी तबाही हुई है । इस लिये भरतपुर और सवाई माधोपुर के जिलोके लिएजो व्यवस्था आपने अभी तक की है वह ना काफी है और काफी असंतोशजनक है । जो भी सडकें टूट गई हैं उन के लिये आप वे कोई प्रावधान पूरी तौर पर नही किया है, खाद बीज का इतजाम नही हो पाया है, जो तालाब टूट गये है उन के रिपेयर्स भी जिस तेजी से किये जाने चाहिए नही किये गये है । इस लिये राजस्थान के इन दो जिलो के लिये, जो फ्लड्स से प्रभावित है , सवाई माधोपुर, भरतपुर और जयपुर का एक हिस्सा, मेरा सब-डिवीजन भी, इन के लिये अधिक सहायता दी जानी चाहिये । जो कारगार कदम उठाये जाने चाहिये और उनके बारे म जो व्यवस्था की जानी चाहिये उसके बारे मे बडा असंतोष है । जो बीज आप दे रहे है उस के बारे मे लोगो मे बडी चिन्ता है, वह बीज आप जिस कीमत पर दे रहे है उस के बारे मे लोग कहते है कि वह बाजार म ज्यादा सस्ते भावो पर मिल सकता है आप महगे भाव पर बेच रहे हैं । मेरी समझ मे नही आता कि अगर बाजार स सस्ते भाव पर वह बीज मिल सकता हे तो आप उन को महगा बीज देने के लिए मजबूर कैस कर सकते है यह वाजिब नहीं है । इस चीज पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

[श्री नवल किशोर शर्मा]

इन शब्दो के साथ मे वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उम्मीद करता हू कि शायद वह कोई संतोषजनक बात कहेंगे जिस से लोगो को राहत मिलेगी ।

श्री बी आर० शुक्ल (बहराइच): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। और इस अवसर का उपयोग मैं कुछ विशेष बातों की तरफ ध्यान दिलाने के लिये करना चाहता हूं जो हमारे उत्तर प्रदेश के सामने है।

... बजट की मांगों का समर्थन करना ही चाहिए क्योंकि उस के बगैर सरकार का काम नहीं चल सकता लेकिन सन् 1972 में यह देखा गया है कि सारे देश में एक आर्थिक बेचैनी की लहर फैली हुई है। कुछ कारण तो ऐसी हैं जो प्रकृति द्वारा पैदा हुए हैं जैसा हमारे माननीय सदस्य श्री नवल किशोर शर्मा ने अभी बतलाया कि कहीं पर अनावृष्टि हुई है, और कहीं पर बाढ़ के कारण स्थिति गम्भीर हो गई है। अधिकांश भागों में मानसून की असफलता के कारण अन्न पैदा नहीं हो रहा है। यह तो प्रकृति के कारण हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से शासन की ओर से आर्थिक स्थिति का मुकाबला किया जा रहा है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह कारगर कदम नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूं उस का कारण देखिये। जहां देश में बारिश हुई भी है तो भी उस सम्पूर्ण पानी का इस्तेमाल सिंचाई साधनों के लिये नहीं किया जाता। मैं उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी अंचलों की ओर आप का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सन् 1971 से बराबर इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि वहां पर नलकूप बनाये जायें, लेकिन सरकार की ओर से बराबर यह कहा जाता है कि तराई का यह क्षेत्र ऐसा है जिस का धरातल ठीक नहीं है। जमीन काफी मजबूत नहीं है जिस के कारण ट्यूबवेल की बोरिंग नहीं हो सकती। इस आधुनिक युग में चन्द्रलोक तक लोग पहुंच सकते हैं लेकिन पृथ्वी के अन्दर नलकूप वह नहीं डाल सकते हैं यह मेरी समझ में बात नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की ओर से यह बराबर कहा गया है कि डीप बोरिंग करने के लिये रिग मशीनों की आवश्यकता है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि इस देश से रिग मशीन बंगला देश को भी भेजी गई, पारसाल जब साइक्लोन आया तब उड़ीसा में उत्तर प्रदेश से रिग भेजी गई, लेकिन सम्पूर्ण उत्तर पूर्व का जो तराई का इलाका है वहां पर कहीं भी नलकूप के निर्माण की व्यवस्था नहीं है। वहां अनुसन्धानात्मक नलकूप के निर्माण की आवश्यकता है यानी कि एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल का कांस्टक्शन होना चाहिए। एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल कैसे बनेंगे? उस के लिए ज्यालाजिकल सर्वे विभाग की मशीनें हैं, उन का उपयोग करके डीप बोरिंग किया जाना चाहिए। जब उस विभाग से कहा जाता है वह कहते हैं कि हमारे विभाग में यह मशीन नहीं है, दूसरे विभाग से कहते हैं तो वह भी कहते हैं कि हमारे यहां नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जब देश में खाद्यान्नों की स्थिति खराब हो रही है और हमको हरित क्रान्ति कायम रखनी है तो यह नितांत आवश्यक है कि जो भी उपजाऊ प्रदेश हैं, जहां पर धरातल के नीचे पानी उपलब्ध है उस पानी का उपयोग

किस तरह से किया जाय, नलकूप कसे बनाए जाए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और यह कोई वजह नही है कि डीप बोरिंग मशीन रिग यहा नही मिलती है या वहा नही मिलती है । मैम्बर पार्लियामैंट यदि इस प्रश्न को उठाते है तो कहा जाता है कि केन्द्र की जिम्मेदारी नही है, सिंचाई और बिजली की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेशो की है। सारे देश मे एक डायार्की सी चल रही है चाहे वह शिक्षा विभाग हो, नहर नलकूप या बिजली विभाग हो । यह मैटर और स्टेट दोनो का कनकरेट सबजैक्ट है और इसी द्वन्द के कारण मै समझता हूं कि पार्लियामैंट के सदस्य अपना कर्त्तव्य आज देश के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति निभा नही पाते है सर्वथा असमर्थ रहते है । यहा जब प्रश्न पूछा जाता है है तो पहले तो उसको एडमिट ही नही किया जाता है इस वास्ते कि यह स्टेट सबजैक्ट है । बडी खीचातानी के बाद एडमिट होता है । मैं समझता हू कि एक इनहैरेट डैफीशेंसी हमारे प्रोसीजर मे है जिस के कारण जो कनकरेट लिस्ट का सबजैक्ट है उसके बारे में हम कुछ नही कर पाते । उत्तर प्रदेश मे खास तौर से बहराइच गोंडा, बस्ती, देवरिया इनके जो तराई के प्रदेश हैं यहा पर रिग मशीन जल्दी से जल्दी भाग करके ट्यूबैल के निर्माण का काम लेना चाहिये ।

दूसरी चीज 1971–72 के वित्तीय वर्ष में तीन लाख रुपये का प्रावधान किया गया था कि बहराइच जिले में विछिया को कोड़ियाल घाट जो लखीमपुर और बहराइच जिले के बीच मे उत्तर पूर्वी रेलवे लाइन पर जुड़े हुए नही हैं उनको जोडने को व्यवस्था की जाए । खद की बात है कि आज उस दिशा मे केवल सर्वेक्षण हुआ है । सर्वे के काम के अलावा और कोई काम नही हुआ है । यहा जो रुपया हम साल हर बजट मे रखते है अगर उसका उपयोग नही होता है तो इस बात का जस्टिफिकेशन है कि साल व साल अनुपूरक ग्राट के के रूप मे फिर से रुपया मागा जाए ? होना तो यह चाहिये कि जो पया किसी कामके लिए निकले अगर वह काम नही होता तो रुपया तो लैप्स हो जाता है और दूसरी ओर हम टैक्स के रूप मे या दूसरे ढग से और रुपया निकालना चाहते है तो यह दुर्व्यवस्था है, नही होनी चाहिये ।

तीसरी चीज आप खाद्यान्न का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे है । बहुत अच्छी स्कीम है । खास तौर से इस सदन के व लोग जोकि समाजवादी व्यवस्था मे विश्वास करते है व यह चाहते कि राष्ट्रीयकरण हो ताकि सस्ता गल्ला सस्ता कपडा, सस्ता मकान, सस्ती दवाइया सस्ती शिक्षा सब लोगो को उपलब्ध हो सके । लेकिन मै दावे से कहता हू कि एक ओर तो फूड कारपोरेशन सारे गल्ले को सस्ती कीमत पर अर्जित करता है लेकिन जब वितरण का प्रश्न आता है कि गरीबों को सस्ते गल्ले की दुकानो से सस्ते भाव पर गल्ला , शक्कर मिले तो आप यह माने कि कही भी आज वह उपलब्ध नही है । यह सिर्फ कागज पर दिखावट है । जो गरीब है, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं मदद करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर या कही और कितनी ही जगहो पर हमारी सारी स्कीमें

[श्री बी० आर० शुक्ल]

जकड़ी पड़ी हैं और हमारे सारे बजट का जो लाभ होना चाहिए वीकर सैक्शन आफ सोसाइटी को वह उसे नहीं मिल रहा है। शक्कर का ब्लैक शहरो के किनारे चन्द मुनाफाखोर लोग करते हैं और दूसरे लोग चिल्ला रहे हैं कि शक्कर नही मिलती है और जो गरीब है वह बेजबान है उसके लिए कोई कहने वाला या सुनने वाला नही है। केवल कागज पर समाजवाद की परिपुष्टीकरण करने मे या बड़ी बडी स्कीम बनाने से समाजवाद नही आएगा उसके लिए आवश्यक है कि सारा शासन वीक सोसाइटी ओरिएंटिड होना चाहिये नौकरशाही के लिए आदेश होना चाहिए कि निर्धारित समय मे अगर वह जो स्कीम दी गई है उसका असली जामा पहनाने से नाकामयाब होते है तो उन की तरक्की रुक जाएगा। जब तक टास्क ओरिएंटेड, रिवार्ड ओरिएंटेड और पनिशमेंट ओरिएंटेड काम नही होगा तब तक कोई काम पूरा नही हो सकता।

मैं आप का अधिक समय नही लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि शासन सुदृढ़ हो बजट हम लोग पास करें लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर नही कर पाते है तो कोई वजह नही है कि बार बार रुपया दिया जाय और वह लैप्स हो जाय या ब्लैक मनी की शक्ल मे रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वालो की जेब म वह बराबर जाता रहे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): I am thankful to the hon. Members who have participated in this debate. Two of my colleagues have already intervened in the debate on the specific points hon. Members raised, pertaining to the Demands concerning their Ministries and consequently, my responsibility has been considerably lightened.

This is the second batch of Supplementary Demands during the present financial year. The present batch of Supplementary Demands involve an additional expenditure of Rs 309.77 crores, of which Rs. 2.18 crores are on Revenue Account, Rs. 55.41 crores on Capital Account and Rs 252.18 crores for disbursement of loans and advances. The additional requirements of Rs 309.77 crores will be set off to the extent of Rs 23.87 crores on account of additional receipts and recoveries on capital account. The net cash outgo arising from these Supplementary Demands for Grants would, thus amounts to Rs 285.90 crores. Two batches of Supplementary Demands taken together will involve a total net cash outgo of Rs. 333.22 crores.

The speeches of the hon. Members, Shri Nawal Kishore Sharma and Shri Shukla and some other hon. Members have provided the necessary background in which these Supplementary grants are being sought from this hon. House. The House had also the opportunity to discuss the price situation and in the discussion of the price situation, the entire economy of the country was discussed by the House and, therein, the Minister of Agriculture has explained the agricultural situation. I am referring to this because one hon. Member, Shri Rao Birender Singh has said that our entire agricultural strategy has failed. This is not a correct statement of facts. That, the House knows. As a result of the green revolution we have able to ... (*Interruptions*).

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) The prices have gone up by 11 per cent You talk of green revolution!

SHRI K R GANESH He knows only one revolution in which he has failed failed miserably

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar) When we are thinking of importing foodgrains, better we talk less of green revolution

DR KAILAS (Bombay South) You do not follow what he is saying Please understand

SHRI JYOTIRMOY BOSU Your Chief Minister, Mr Sidhartha Shankar Ray, has rightly spoken out

SHRI K R GANESH I was referring to a speech of an hon Member about the failure of the entire agricultural strategy As I was just telling, during the price situation discussion the Agriculture Minister explained that as a result of the strategy undertaken by the Government we were in a position to have a stock of 9 million tonnes of foodgrains It is a fact that there has been drought it is also a fact that there has been large-scale flood in this country, it is something for which this Government is not responsible To meet the crisis the national calamities, as stated by the hon Finance Minister,—various steps have been taken and one should not overlook the progress that has already been made in this direction It is a fact that the face of Indian agriculture has changed Nobody says that green revolution has succeeded completely There are still certain problems But nobody can deny that Indian Agriculture has changed and only those who want to remain in their own positions will overlook this fact It is a fact that green revolution has got to go to course grains There are various problems which we have got to take into account We have to take into account changes due to land reforms All these things are being attended to

The fact remains that due to the particular strategy adopted, certain progress has been made Our scientists have proved and our farmers have adapted themselves to the use of high-yielding varieties of seeds and it is found that they suit our own conditions

As we have succeeded in the past we have no doubt, we will be able to succeed in the future and meet this crisis which we are faced with today

Some Members said that the entire economy has gone out of gear Some points were made that we are facing tremendous monetary and other difficulties These are various points which were already discussed when we took up the Price-rice discussion

Sir the Indian economy has been able to stand up and face stresses and strains forced on it It stood up to the strain due to Bangladesh crisis and it has got the capacity to stand up again and face the present situation What is needed is an element of confidence We should mobilise all the resources within the country so that we may be able to meet this crisis

The very fact that we have devoted so much for the purpose of crash programme indicates that we are determined to leave no stone unturned in this respect In regard to agriculture and industry, in both the fronts, we have taken steps so as to strengthen the economic base so that we may be able to tide over the situation

My friend Mr N K Sharma said about Rajasthan We have provided quite a lot of substantial help to Rajasthan and if something more is necessary we will try to do what we can within the allotted schemes

Shri Birender Singh Rao had raised another question with regard to a small grant which we are seeking The only point that I wish to make

[Shri K. R. Ganesh]

is that the Army Officer who was retired on the advice and on the instructions of the Central Vigilance Commissioner.

The hon. Member from the DMK had raised a question about the Salem steel plant. I have it on the authority of the Minister of Steel and Mines that now it is expected that the Salem steel plant is expected to be completed in six years, that is, by the end of 1978 or early 1979. What has been given here in the booklet is a typographical error which I have been asked to correct.

These are some of the points which hon. Members had raised. These Demands relate to calling for the approval of the House of various items which go to strengthen the economy of the country, and with the allotments already available to the Government, we shall be able to make an impact and meet the situation that is there.

With these words, I commend these Demands for the approval of the House.

SHRI BHOGENDRA JHA: He has not answered some of the important points that I had raised. I would like to know whether our Government is advising the persons of Indian origin residing in Uganda or Kenya or such other countries to seek British passport or British Indian citizenship....

MR. DEPUTY-SPEAKER: In the first place, this question does not relate to the Supplementary Demands.

SHRI BHOGENDRA JHA: They are coming, and if they do, naturally, we shall support....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Secondly, I do not think that there is any such item in the List of Demands....

SHRI BHOGENDRA JHA: I had raised this in my speech.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): There is a specific Demand relating to relief to the people who are coming from Uganda.

SHRI BHOGENDRA JHA: Then there was a question about the crash programme on which we were spending Rs. 150 crores. This question had been raised by the hon. Member from Rajasthan also. Why not take advantage of this and have early completion of the Rajasthan canal? Similarly, the Gandak and the Western Kosi canals could be completed so that the gain can be durable and dependable also.

Thirdly, there was a specific allegation made against the Agriculture Minister about his violating the Land Ceiling Act in his own personal case. There is a finding by the committee appointed by the Assam Legislature that particularly in his own case, he has flouted the Land Ceiling Act, and, therefore, there was a demand for his resignation. Either the hon. Minister of State in the Ministry of Finance should reply or the Minister of Agriculture should reply or else the hon. Finance Minister should reply

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry for my earlier observation. I have seen the booklet, and I find that there is a provision in regard to persons coming from Uganda.

SHRI K. R. GANESH: As far as the question of Uganda is concerned, I do not know how my hon. friend is raising this question. I do not know how it helps the Indian and Asian residents who are leaving Uganda, because what he is asking amounts to this. He wants to know whether the Government of India have advised them that they should accept the citizenship of the....

SHRI BHOGENDRA JHA: They sought British citizenship on their own. That is causing trouble today. Again, the trouble is going to extend

to Kenya and the day after tomorrow it may spread to some other country If they come, we shall receive them, but what is our advice to them.

MR. DEPUTY-SPEAKER How can the hon Minister say anything on this? That is a much bigger question than the question of Demands It is a big question of policy.

SHRI JYOTIRMOY BOSU But he is also a big Minister.

SHRI K R GANESH It is a very dangerous question also, and I do not think that in a situation like this it is the intention of the hon Member to provide an *alibi* to the acts that are going on....

MR. DEPUTY-SPEAKER I think it is best for Government to think about it. Let him not say anything now.

SHRI K R GANESH Then he had also talked about the crash programme He has made a suggestion about the various other schemes which will help in increasing agricultural production.

SHRI JYOTIRMOY BOSU I had quoted extensive figures to show that the money that was being given was not being spent For instance, I had referred to the amounts spent under the crash programme for drought-prone areas.

SHRI K R GANESH Those matters are engaging continuously the attention of the Planning Commission, and on a national scale, provisions are made as far as this is concerned . .

SHRI JYOTIRMOY BOSU· But nothing is happening. Are you satisfied with the reply, Sir?

SHRI BHOGENDRA JHA: Very serious allegations had been made against the Agriculture Minister....

SHRI K R. GANESH: He has made some specific charges as far as the Minister of Agriculture is concerned The Minister of Agriculture was here He has taken note of that. But I must clarify that Shri F. A. Ahmed, Minister of Agriculture, is committed, as far as land reforms are concerned, and it is wrong to say that he has been scuttling or was trying to sabotage land reforms.

SHRI BHOGENDRA JHA: Without knowing it, he is contradicting me.

MR DEPUTY-SPEAKER· It becomes another debate now There is an order of debate

SHRI BHOGENDRA JHA: I will read only one sentence from the reported recommendation made unanimously by a Committee appointed by the Assam Legislature led by the Revenue Minister of Assam The report was submitted on 22 October, 1971 It reads.

> "Shri Fakruddin Ali Ahmed who was a member of the Cabinet at that time and, therefore, had overall responsibility for implementation of the Government's policy does not seem to have been helpful in the quick and proper implementation of the ceiling law, particularly in his own case".

This is the quotation.

SHRI S M BANERJEE *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please I am on my legs.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: This is a serious matter

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order I just want to draw attention to the rule regarding cases like this. This allegation has been made before. I understand it is not made for the first time now in the course of the debate.

SHRI BHOGENDRA JHA: It was made in the course of this debate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me finish. It is on record. Nothing can be done about it now. But I would just like to draw attention to the rule which says:

> "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply".

An allegation has been made. You should have done it under this rule. But it has been made and it is on record. I think the next thing is that Government will take note of this, they will make such investigations as necessary and come before the House with a statement. I do not see how you can expect the Minister of State in the Ministry of Finance now to give a reply to that.

SHRI BHOGENDRA JHA: Let Government come before the House with a statement.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: This was made long ago, once or twice before.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let us not go on with this now.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Why did he not make a statement last time?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Why are you anxious that they should take shelter under your Table? Are you giving them yawning space to take shelter....

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. You cannot expect the Minister of State in the Finance Ministry to go into that just now. You have made an allegation on the floor of the House. Government have taken note of it. It is for them to come forward and say what they have to make in the matter. Nothing will come out of it just now.

SHRI S. M. BANERJEE: This allegation has not been made by Shri Bhogendra Jha. He has in his wisdom read out from a particular report which was made in which this allegation has been made by the members of the Assam Legislature.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All this is on record.

SHRI S. M. BANERJEE: It is the finding of that Committee. I can understand the rule you quoted. No opportunity was given to the hon. member to make any allegation. He was just reading from that report.

15 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It comes to the same thing. Now, all this is before the Government and it is for them to consider and come before the House if they want.

SHRI S. M. BANERJEE: They should resign. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Naturally; I cannot compel them. (*Interruptions*). Order, please. Now, there are certain cut motions moved by Mr. Jyotirmoy Bosu. Shall I put all of them together to the House?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: If you so like.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall put all of them together.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column

of the order paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of the following demands entered in the second column thereof:—

Demands Nos. 53, 63, 113, 129, 131 and 136."

The motion was adopted.

[The Motions for Supplementary Demands for Grants, which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below—Ed.]

Demand No. 53—Industries

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,16,79,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1973, in respect of 'Industries'."

DEMAND No. 63—DEPARTMENT OF REHABILITATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1973, in respect of 'Department of Rehabilitation'."

DEMAND No. 113—LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,18,00,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1973, in respect of 'Loans and Advances by the Central Government'."

DEMAND No. 129—OTHER CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 48,51,93,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1973, in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Steel and Mines'."

DEMAND No. 131—OTHER CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 6,89,00,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1973, in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Tourism and Civil Aviation'."

DEMAND No. 136—CAPITAL OUTLAY ON POSTS AND TELEGRAPHS (NOT MET FROM REVENUE)

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1973, in respect of 'Capital Outlay on Posts and Telegraphs (not met from Revenue)'."

15.01

APPROPRIATION (NO. 5) BILL*, 1972

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1972-73.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27th November, 1972.